an>

Title: Regarding revision of salary of the employees working at Bharat Wagon Limited at Mokama and Muzaffarpur factories in Bihar.

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष महोदया, सरकार एक तरफ स्किल इंडिया हुनर से देश के बेरोजगारों और मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहती है। बिहार में भारत वैगन मुजफ्फरपुर और मोकामा दोनों इकाई पारम्परिक रूप से वैगन विनिर्माण से जुड़े कारखाने हैं। अभिविन्यास, संयत्र एवं यंत्र-समूह तथा स्थान, इस उत्पाद के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त रहा है।

मेरा आपसे आग्रह है कि यहां रेलवे मंत्री मौजूद हैं। 1978 में दोनों निजी क्षेत्र रुग्ण वैगन का विनिर्माण हुआ था। लेकिन आज भारत वैगन कंपनी मोकामा और मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों की जो स्थिति है, वह रेलवे के उदासीन रवैये के कारण दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वर्ष 1989 से 1999 तक कई उत्पादक पुरस्कार से सम्मानित एवं लाभांश के बावजूद भी 1997 का वेतन पुनरीक्षण नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 2008 में रेलवे द्वारा शून्य बैलेन्स पर इसे अधिग्रहित किया गया था, इसके बावजूद वेतन पुनरीक्षण एवं बुनियादी सुविधाएं आज तक बहाल नहीं होना भारत सरकार के इन वैगन के कारखानों की इससे बड़ी समस्या कुछ नहीं हो सकती। मैं आपका ध्यान बंगाल की दो कंपनियों ब्रैथवेट और बर्न स्टैंडर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें रेलवे द्वारा 2010 में अधिग्रहित कर वेतन पुनरीक्षण एवं बुनियादी सुविधाएं दी गई। जहां 700 कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनों 74 एवं 84 (एमपीओएव) वैगन की मरम्मत की गई, वहीं भारत वैगन ने मात्र 300 कर्मचारियों की मदद से मोकामा 59 एवं 76 वैगन की मरम्मत कर अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं लगन को दर्शाया है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक तरफ मेहनत के बदले बंगाल की दोनों कंपनियों में नियमित रूप से वेतन का भुगतान होता है और वहीं पर बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जो हमारा मोकामा है, उसके पुनर्निमाण के लिए सरकार को रिव्यू करना चाहिए, परंतु वह न करके वहां के कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां की स्थिति बहुत ही बदतर है। जबकि देश के मानचित्र में मुजफ्फरपुर और मोकामा का निर्माण कार्य सबसे उत्कृष्ट रहा है।

मैं रेल मंत्री का ध्यान इन दोनों के साथ-साथ मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं, यह फैक्टरी पूरी बन गई है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। स्लीपर फैक्टरी बन गई, उसमें लागत लग गई, भारत सरकार का पूरा पैसा लग गया और आज तक वह चालू क्यों नहीं हुई? इन तीनों मुद्दों पर मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर, मोकामा और मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदया आपका संरक्षण चाहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह मजदूरों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बिहार सबसे अधिक माइग्रेट है, अभी मंत्री महोदय ने भी कहा है। इसलिए मोकामा, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका रिव्यू किया जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री राजीव सातव को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) :** अध्यक्ष महोदया, जिस विषय को राजेश रंजन जी ने उठाया है, यह सचमुच अपने आपमें एक महत्वपूर्ण विषय है, चाहे मोकामा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी का मुद्दा हो या बेला का मुद्दा हो, जिसका निर्माण हो चुका है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की दो सबसे बड़ी योजनाएं मधेपुरा और मढ़ौरा में रेल कोच फैक्टरी स्वीकृत की हैं। ये सभी कार्यक्रम रेल मंत्रालय के अधीनस्थ हैं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं और निश्चित रूप से इन सभी पर भारत की सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, इसमें जो भी पहल हो सकेगी, जैसे जो बंद हैं या जिनकी स्थिति खराब है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जो 40 हजार करोड़ की लागत से मधेपुरा और मढ़ौरा की रेल फैक्टरी इंजिन के कारखाने की स्वीकृति हो चुकी है, उसका समझौता हो चुका है। इसके अलावा बिहार के लिए जो विशेष पैकेज की बात की गई थी, उसी के तहत भारत सरकार ने इन कार्यों की शुरूआत कर दी है।